>

Title: Need to formulate a comprehensive plan for the welfare of the poor in the country.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार हरदम बढ़ती विकास दर और आम आदमी की बात करती है। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जो सर्वे किया उसमें कहा गया है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के 22 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। इतना ही नहीं विश्व की कुल आबादी के 25 प्रतिशत भुखमरी के शिकार लोगों का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत में ही रहता है। योजना आयोग ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 27 फीसदी बताई। सरकार द्वारा गठित डॉ0 सुरेश तेंडुलकर ने इसे नकार कर देश में 37 प्रतिशत गरीब होने का अनुमान निकाला। अर्जुन सेन गुप्ता समिति तो 70 फीसदी गरीब होने का निष्कर्ष निकालते हैं। इसका मतलब देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, देश के विकास में विषमता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का विरोध करती है।

"सेव द चिल्ड्रन" रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना पांच हजार से भी अधिक बच्चे कुपोषण के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं।

भारत जैस विकासशील देश में प्रतिवर्ष 25 लाख शिशु अकाल मृत्यु के भेंट चढ़ जाते हैं और खाद्यान्न उपलब्धता में हो रही कमी और महंगाई के कारण भोजन पर कमाई का 55 से 70 फीसदी तक खर्च करना देश में गरीबों की उपेक्षा की कहानी को दोहराता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका गंभीर संज्ञान देकर गरीबों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए घोषणा के बजाय विशेष अभियान और प्रत्यक्ष कार्ययोजना चलाये।